

अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था (Economics and Economy)

➤ अर्थव्यवस्था (Economy)

- सीमित संसाधनों से अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। उनकी पुस्तक *Wealth of Nation* 1776 में प्रकाशित हुई। उन्होंने कर का सिद्धांत दिया। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य / कौटिल्य अथवा विष्णु गुप्त को कहते हैं एवं उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी, जिनका प्रयोग प्रशासन हेतु किया जाता

था। भारतीय आर्थिक नीति के जनक **M. Visves Varaya** को कहते हैं एवं उन्होंने **Planned Economy for India** नामक पुस्तक लिखी।

➤ अर्थव्यवस्था का क्षेत्रप

- अर्थव्यवस्था में आय के माध्य को क्षेत्रप कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटते हैं।



आर्थिक क्रियाओं के आधार पर

1. प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector)

- जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं एवं इसमें भूमि, उत्खनन तथा उससे संबंधित गतिविधियाँ शामिल होती हैं।

Ex :- कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन।

- जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें लाल कॉलरधारी कहते हैं।

2. द्वितीयक क्षेत्र (Secondary sector)

- इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है। इसमें निर्माण तथा विनिर्माण दोनों होता है एवं यह प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है और अंतिम वस्तुओं (उपयोग हेतु) में परिवर्तित करता है।

Ex :- वस्तु, उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, विद्युत इत्यादि।

- जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें नीली कॉलरधारी कहते हैं।

3. तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)

- इसमें नौकरी, व्यापार, दुकान को शामिल करते हैं। इसे 'सेवा क्षेत्र' भी कहते हैं।

Ex :- परिवहन, Hospital, कोचिंग, नेता, खेल, Communication, Bank, शिक्षा, नौकरी।

- जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें सफेदपोश श्रमिक कहते हैं।

Note :- सेक्टर में लोग बहुत कम लगे होते हैं। किन्तु आय बहुत अधिक होती है। जैसे-जैसे लोगों का विकास होता जाता है वह प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर तृतीयक क्षेत्र में चले जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान समय (2022) में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मात्र 21.82%, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 24.23% तथा तृतीय सेक्टर का योगदान 53.09% है।

कार्य के आधार पर

1. संगठित क्षेत्र

- जिसमें नौकरी की शर्त, समय और वेतन तीनों ही निश्चित हो उसे 'संगठित क्षेत्र' कहते हैं।

Ex :- बड़े कम्पनी की नौकरी, सरकारी नौकरी।

- संगठित क्षेत्र में सार्वधिक रोजगार रेलवे तथा सेना में दिया है।

2. असंगठित क्षेत्र

- इसमें नौकरी का समय वेतन तथा छुट्टी तीनों ही अनिश्चित रहता है। सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र कपड़ा उद्योग है।

Ex :- प्राइवेट क्षेत्र, कृषि, दुकान।

स्वामित्व के आधार पर

1. निजी क्षेत्र (Private Sector)

- इसके सभी क्षेत्र पर निजी व्यक्ति का हाथ होता है। इसे Private (Pvt.) कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना है। पूंजी के आधार पर भारत की सबसे बड़ी Private कम्पनी Reliance जबकि कर की क्षमता के आधार पर सबसे बड़ी कम्पनी TATA है।

2. सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector)

- इस पर पूरी तरह सरकार का अधिकार होता है। इसे Public sector भी कहते हैं यह विकास तथा समाज कल्याण के लिए होता है। सबसे बड़ी Public क्षेत्र की कम्पनी रेलवे तथा महारत्न है।

3. संयुक्त क्षेत्र (Joint Sector)

- इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों की भागीदारी होती है। अतः इसे public private partnership कहते हैं। वर्तमान में भारत में सबसे तेजी से ppp का विकास हो रहा है। उदाहरण- मेट्रो

4. सहकारी क्षेत्र (Co-operative Sector)

- जब किसी कम्पनी को दिशा निर्देश सरकार देती है उसे co-operative कहते हैं।

Ex :- Co-operative Bank co-operative का संचालन कई लोगों के समुह द्वारा होता है।

उत्पादन के चार कारक

1. पूँजी

- उत्पादन में लगाया गया धन पूँजी कहलाता है यह ऋण के रूप में भी हो सकता है।

2. भूमि

- जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है उसे भूमि कहते हैं। यह किराया के स्थान पर भी हो सकता है।

3. श्रमिक

- वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूरों को श्रमिक कहते हैं।

4. उद्यमी

- कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसे उद्यमी कहते हैं।



संसाधनों के स्वामित्व या उत्पादन के साधन
या सरकार की भूमिका के आधार पर

पूंजीवादी

- ❖ अहस्तक्षेप (बाजार शक्तियाँ-मांग व आपूर्ति) व निजी स्वामित्व
- ❖ अमेरिका, कनाडा आदि।

समाजवादी

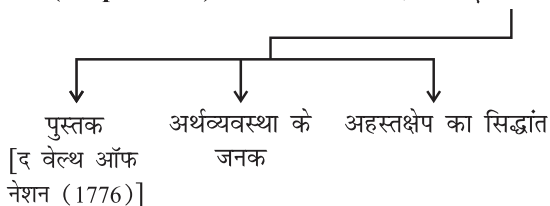
- ❖ सरकारी हस्तक्षेप व स्वामित्व
- ❖ क्यूबा, उत्तर कोरिया आदि
- ❖ इसे राज्य आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है।

मिश्रित

- ❖ सरकार व निजी क्षेत्र की सहभागिता
- ❖ भारत, स्वीडन, फ्रांस आदि।

पूंजीवाद अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy)

प्रस्तुतकर्ता (Propounded)-स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ।



- इन्होंने अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र को 'धन का विज्ञान' कहा है।

➤ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था

- जब उत्पादन के सभी 4 कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जापान, U.S.A., सिंगापुर, चीन, पूंजी, अर्थव्यवस्था में विकास तेजी

विशेषता- प्रतिस्पर्धा।

उद्देश्य- अधिकतम लाभ।

आर्थिक स्वतंत्रता।

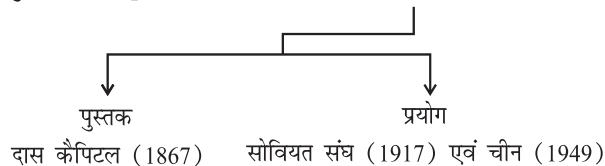
उपभोक्ता के पास विकल्प।

आर्थिक समानता।

से होता है। इसमें गरीब को ध्यान में न रखकर बाजार को ध्यान में रखा जाता है।

समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy)

प्रस्तुतकर्ता (Propounded)– जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स (1818-1883)



विशेषता–

उद्देश्य– जनकल्याण।

बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव।

केन्द्रीय आर्थिक नियोजन।

बाजार कीमत के स्थान पर प्रशासकीय कीमत।
आर्थिक समानता।

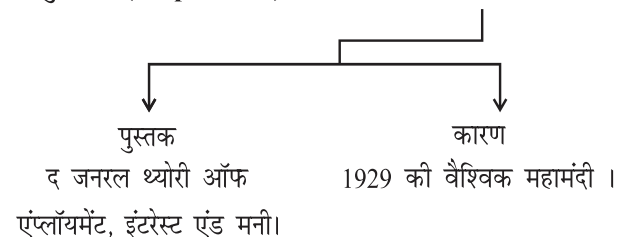
➤ समाजवादी अर्थव्यवस्था

- जब उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार का अधिकार हो तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाएँ (उत्पादन, उपभोग, वितरण व विनिमय) को संचालित करती है।

उदाहरण– सोवियत संघ, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया।

मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)

प्रस्तुतकर्ता (Propounded)– ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मिनार्ड कोस।



➤ मिश्रित अर्थव्यवस्था

- जब उत्पादन के चारों कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह पूँजीवादी तथा राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है।

Ex :- भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका।

➤ द्वैध अर्थव्यवस्था (Dual Economy)

- वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें परम्परागत तथा आधुनिक दोनों विधियों का प्रयोग हो उसे द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं।

Ex :- India.

➤ समांतर अर्थव्यवस्था (Parallel Economy)

- कालाधन अत्यधिक बढ़ जाने को समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी होती हैं।

➤ काला धन (Black Money)

- वैसा धन जिस पर Tax नहीं दिया जाता है उसे कालाधन कहते हैं। कालाधन की जानकारी सरकार को नहीं रहती है।

विशेषता–

उद्देश्य– जनकल्याण।

कल्याणकारी राज्य।

आर्थिक नियोजन।

सामाजिक न्याय।

□□□

Most Trusted Learning Platform

KHAN SIR

02.

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) (Gross Domestic Products)

➤ सकल घरेलू उत्पाद [GDP (Gross Domestic Products)]

- एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा के मूल्य को GDP कहते हैं। सीमा के बाहर उत्पादित वस्तु को G.D.P. में शामिल नहीं किया जाता है।

जैसे— tata = 800 Man (विदेशों में भारतीय) = 150
L. G = 300 GDP = 1100

➤ सकल राष्ट्रीय उत्पाद [GNP (Gross National Products)]

- यह पैसा राष्ट्र के काम का होता है। इसमें केवल भारतीय आय को शामिल करते हैं।

माना भारतीय द्वारा विदेश में अर्जित आय x है, तथा विदेशी द्वारा भारत में अर्जित आय y है, तो—

$$\boxed{\text{GNP} = \text{GDP} (x + y)} \quad \text{Ram} = 150$$

tata = 800

L.G = 300

$$\text{GNP} = 1100 + (150 - 300) = 950$$

Note : $x - y$ को शुद्ध साधन आय कहते हैं।

Case I : यदि $x = y$ हो (संतुलित अर्थव्यवस्था) $\text{GNP} = \text{GDP}$

Case II : यदि $x > y$ हो (लाभ) $\text{GNP} > \text{GDP}$

Case III : यदि $x < y$ (हानि) $\text{GNP} < \text{GDP}$

Case IV : यदि $x = y = 0$ (बन्द अर्थव्यवस्था) $\text{GNP} = \text{GDP}$

Q. GDP तथा GNP का अंतर क्या कहलाता है।

Ans. $\text{GDP} - \text{GNP}$

$$\text{GDP} - (x + y)$$

$$(x - y) = \text{शुद्ध साधन आय}$$

➤ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन [NNP (Net National Products)]

- यह देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है। जब GNP में से मशीनों की टुट-फुट या घिसावट पर आय खर्च को घटा देते हैं, तो उससे NNP मिलता है।

$$\boxed{\text{NNP} = \text{GNP} - D} \quad \text{जहाँ } D = \text{मूल्यहास}$$

tata = 800 Ram = 150

L.G = 300 D = 50

GDP = 1100

GNP = 950

$$\text{NNP} = 950 - D = 950 - 50 = 900$$

Q. GNP तथा NNP का अंतर क्या होता है?

Ans. $\text{GNP} - \text{NNP}$

$$\text{GNP} - (\text{GNP} - D)$$

$$\text{GNP} - \text{GNP} + D$$

$D = \text{मूल्यहास}$

- किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्य प्रति व्यक्ति आय होता है।
- किसी देश के प्रगति को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम GDP होता है।
- मूल्य के आधार पर भारत की GDP छठे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अमेरिका।
- किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत (factor cost) पर निर्भर करती है। कोई भी वस्तु अपने Factor Cost पर बनी रहती है।

$$\text{Price} = \text{Factor Cost (F.C.)}$$

$$\text{MRP} = \text{FC (Factor Cost)} + \text{TAX}$$

$$\boxed{\text{GDP at Market Price (GDP}_{(\text{MP})})}$$

- GDP हमेशा Market Price पर ही निकलता है।

➤ $\text{GDP}_{(\text{MP})}$

- जो Price हमें मिलता है उसमें सरकार द्वारा Tax जोड़कर महंगा कर दिया जाता है या सब्सिडी जोड़कर सस्ता कर दिया जाता है।

$$\text{GDP}_{(\text{MP})} = \text{GDP}_{(\text{FC})} + \text{Tax} - \text{Subsidies}$$

$$\boxed{\text{GDP at Factor Cost (GDP}_{(\text{FC})})}$$

- वास्तविक में GDP की गणना Factor Cost पर ही होनी चाहिए।

$$\text{GDP}_{(\text{FC})} = \text{GDP}_{(\text{MP})} - \text{Tax} + \text{Subsidies}$$

हम जो GDP निकालते हैं Actual में वह Nominal GDP न होकर Real GDP होता है जो किसी न किसी Base Year पर निर्भर करता है।

➤ Nominal GDP

- इसमें उत्पादित वस्तु का चालू वर्ष के मूल्य पर निकाला जाता है।
- जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्यों (चालू कीमतों) पर की जाती है तो उसे Nominal GDP कहते हैं।
- Nominal GDP हमेशा अधिक होती है, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति भी जुड़ी होती है।
- Nominal GDP में Production Value नहीं देख पाते हैं।
- Nominal GDP उस साल के Price पर निकाला जाता है जिस साल की GDP को निकाल रहे हैं।

Pencil	Per Pencil Price	Production	Nominal GDP
2011	5	20	$5 \times 20 = 100$
2012	6	19	$6 \times 19 = 114$
2020	7	18	$7 \times 18 = 126$
2021	10	15	$10 \times 15 = 150$
2022	15	14	$15 \times 14 = 210$

$$\text{Purchasing Power Parity Formula} = \frac{\text{Cost of good} \times \text{in currency 1}}{\text{Cost of good} \times \text{in currency 2}}$$

□□□

Real GDP

- जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष के मूल्य (स्थिर कीमतों) पर की जाती है तो उसे Real GDP कहते हैं।
- इसके आंकड़े विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की सही एवं अधिक वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है।
- जब हम Real GDP को निकालते हैं तो Price हम आधार वर्ष का लेते हैं और Production चालू वर्ष का लेते हैं।
- Base Year = 2011

$$\text{GDP Deflector} = \frac{\text{Nominal GDP}}{\text{Real GDP}} \times 100$$

Pencil	Per Pencil Price	Production	Nominal GDP	Real GDP
2011	5	20	$5 \times 20 = 100$	$5 \times 20 = 100$
2012	6	19	$6 \times 19 = 114$	$5 \times 19 = 95$
2020	7	18	$7 \times 18 = 126$	$5 \times 18 = 90$
2021	10	15	$10 \times 15 = 150$	$5 \times 15 = 75$
2022	15	14	$15 \times 14 = 210$	$5 \times 14 = 70$
			GDP = ↑	GDP = ↓

क्रय शक्ति समर्थ (Purchasing Power Parity)

- यह अंतराष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है।
- यह देशों के बीच वस्तु या सेवा की कीमत में मौजूद अंतर है।
- किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया जा सकता है।
- PPP के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि दो देशों के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति में कितना अंतर या फिर कितना समता मौजूद है।
- PPP द्वारा मुद्रा विनिमय दर को तय किया जाता है।
- PPP के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर है। प्रथम तथा दूसरे स्थान पर चीन अमेरिका है।
- भारत का PPP और अमेरिका के PPP में 17 गुना का अंतर है।
India = US × 17

राष्ट्रीय आय (National income)

- किसी देश के अंदर सभी घटक सरकारी तथा निजी से मिलने वाली कुल आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय बाजार स्तर पर NNP होता है।

राष्ट्रीय आय = NNP – अप्रत्यक्ष कर

- भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। इसकी स्थापना 1951 में हुई। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जो P.C महालनोबिस का जन्म दिवस है।
- भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना 1968 में दादाभाई नौरोजी ने किया। उन्होंने इस समय भारत का प्रतिव्यक्ति आय ₹ 20 निकाला था, जो सालाना था। इन्होंने अपनी पुस्तक Poverty and Unbritish Rule in India में लिखी है।
- वर्तमान में भारत का प्रतिव्यक्ति आय 1 लाख 72 हजार सालाना है। किसी देश के प्रगति को दिखाने का सबसे अच्छा माध्यम प्रति व्यक्ति आय होता है।

$$\text{प्रतिव्यक्ति आय} = \frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}}$$

➤ हिन्दू विकास दर

- हिन्दू विकास दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर कीमतों पर की जाती है।

➤ चालू कीमत

- चल रहे वित्तीय वर्ष को चालू कीमत कहते हैं। इस पर राष्ट्रीय आय सटीक नहीं निकलता है।

➤ स्थिर कीमत

- बीते हुए वर्ष पर निकाला गया राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत कहलाता है। इसके लिए किसी वर्ष को हम आधार मान लेते हैं। भारत का आधार वर्ष 2017-18 है।
- राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत पर NNP को दर्शाता है।

➤ राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ हैं-

1. उत्पादन विधि

- इस विधि में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। यह GDP को दर्शाता है। इसमें दोहरे गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिस कारण अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़ा जाता है।

$$\text{उत्पादन} \rightarrow \text{NNP}_{(fc)} = \text{NNP}_{(mp)} - \text{Tax} + \text{Subsidy}$$

2. आय गणना विधि

- इस विधि द्वारा सभी क्षेत्रों के आय को जोड़ा जाता है। चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन तथा आय दोनों विधि से किया जाता है।

$$\text{NI} = \text{R} + \text{I} + \text{W} + \text{P}$$

आय विधि → भूमि = किराया (R)

पूँजी = ब्याज (I)

श्रम = मजदूरी (W)

उद्यम = लाभ (P)

3. व्यय विधि (Expenditure Method)

$$\text{N.I.} = \text{C} + \text{I} + \text{G} + (\text{x} - \text{m})$$

C = उपभोग

I = निवेश

G = सरकारी व्यय

x = Export

m = Import

(x - m) = शुद्ध निर्यात (Net Export)

4. उपभोग विधि

- इस विधि में उपयोग तथा बचत को जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग विकसित देशों में किया जाता है। बचत विधि तथा मौद्रिक विधि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है।

5. सकल मूल्यवर्धन विधि

गेहूँ	Value Added +500	आटा	Value Added +500	बिस्किट
100 kg		100 kg		1000 Packet
20 Rs.		25 Rs.		5 Rs.
Value 2,000		2,500		5,000

$$\text{N.I.} = 2,000 + 2500 + 5000 = 9500 \text{ Rs.} \times$$

$$\text{N.I.} = \text{Primary Value} + \text{Value added} + \text{value Add} \\ = 2000 + 500 + 2500 = 5000 \checkmark$$

➤ मौद्रिक आय

- किसी श्रम के बदले मिले धन को मौद्रिक आय कहते हैं।

➤ प्रयोज्य आय (Disposable income)

- मौद्रिक आय में से tax घटाने के बाद बचे धन को प्रयोज्य आय कहते हैं। यह पूरी तरह White money होता है।

➤ वास्तविक आय (Real income)

- प्रयोज्य आय में से देनदारी तथा ऋणभार को हटा देने पर बचा हुआ धन वास्तविक आय कहलाता है। महंगाई बढ़ने पर वास्तविक आय घट जाता है।

Q. नितिश ने अनुराधा से ₹ 4000 कर्ज लिये। यदि नितिश की आय ₹ 1 लाख है तथा नितिश पर 30% tax है। इसके सभी आय की गणना किजिए।

Ans. मौद्रिक आय = 1 लाख

$$\text{प्रयोज्य आय} = 1 \text{ लाख} \times 30\% = 70,000$$

$$\text{वास्तविक आय} = 70,000 - 4000 = 66,000 \text{ Ans.}$$

गरीबी (Poverty)

☞ गरीबी उन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है जो व्यक्ति तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाये रखने में आवश्यक है।

गरीबी में पाँच मूलभूत चीजों में से एक या एक से अधिक की कमी से हो जाती है—

- (i) भोजन
- (ii) वस्त्र
- (iii) आवास
- (iv) शिक्षा
- (v) चिकित्सा।

➤ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार

☞ गरीबी निम्नतम जीवन-यापन स्तर करने की असमर्थता है, यानी जब निम्नतम जीवन-यापन स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सके।

➤ विश्व बैंक के अनुसार

☞ वह व्यक्ति जिसकी प्रतिदिन की आय 2 अमेरिकी डॉलर से कम है, वह गरीब है।

➤ वी.एम. और एन. रथ फार्मूला (1971)

☞ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि।

➤ सुरेश तेंदुलकर समिति (2009)

☞ इसमें कैलोरी के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार बनाया गया।

☞ शहरी क्षेत्र में 33 रुपये प्रति दिन और ग्रामीण क्षेत्र के लिये 27 रुपये प्रति दिन से कम खर्च करने वाले लोग गरीब हैं।

➤ सी. रंगराजन समिति (2012)

☞ शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रति दिन और ग्रामीण क्षेत्र के लिये 32 रुपये प्रति दिन से कम खर्च करने वाले लोग गरीब हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय [National Statistical Office (NSO)]

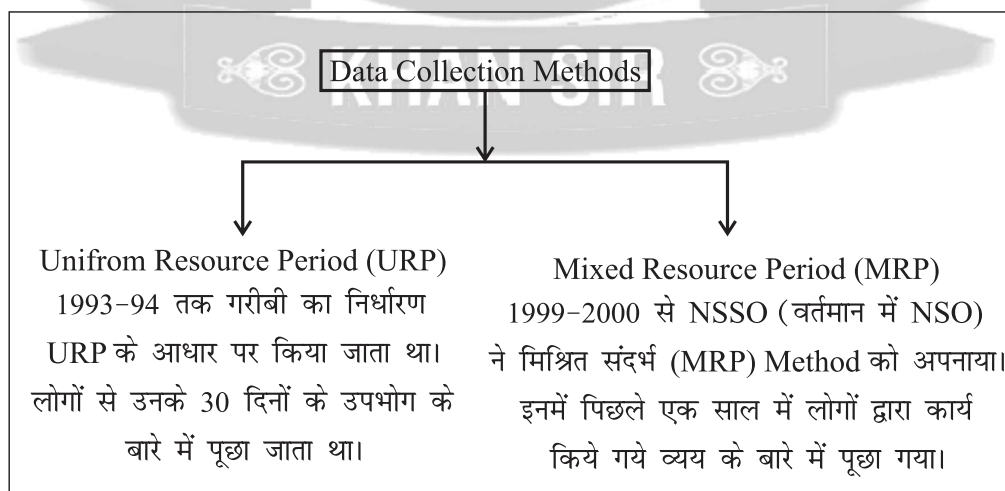
☞ 2019 में NSSO और CSO के विलय से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) का गठन हुआ। 2019 से पहले भारत में गरीबी का अनुमान NSSO द्वारा किया जाता था। जिसकी स्थापना 1950 में हुआ था, जो केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन था।

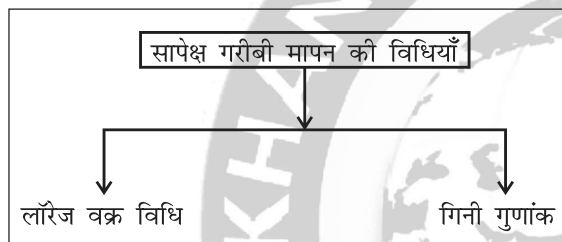
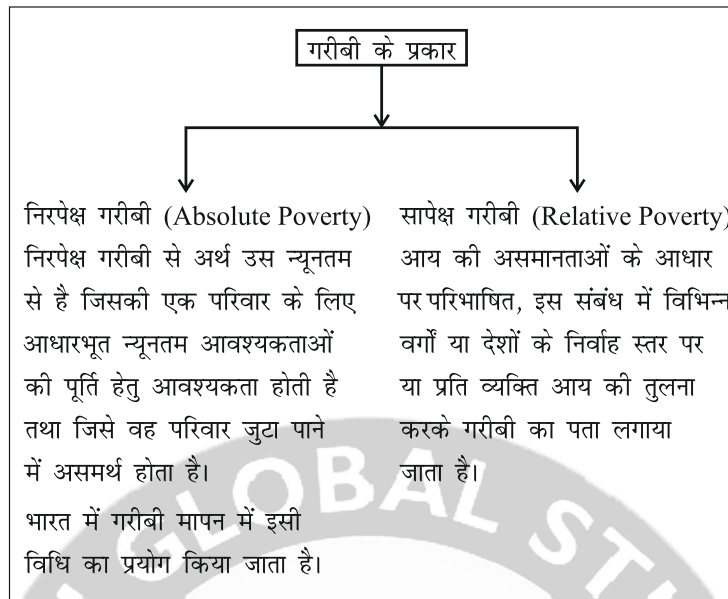
केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)

नीति आयोग

Data Collection Methods



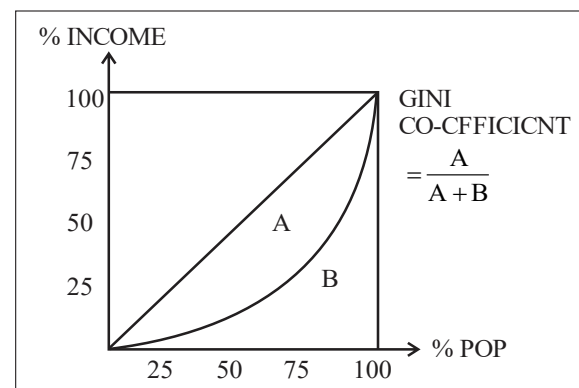
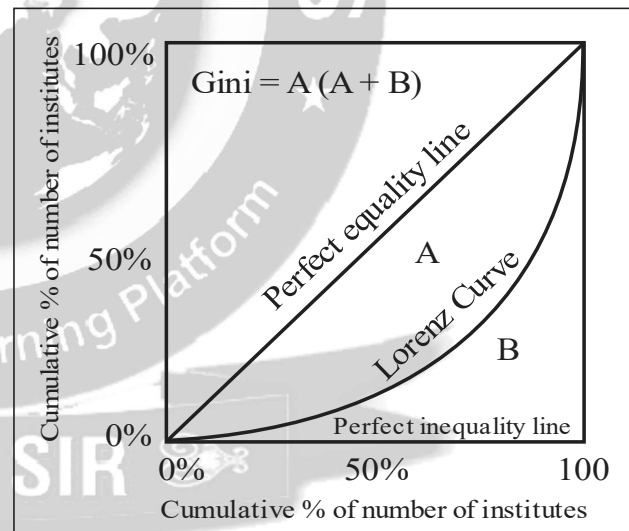
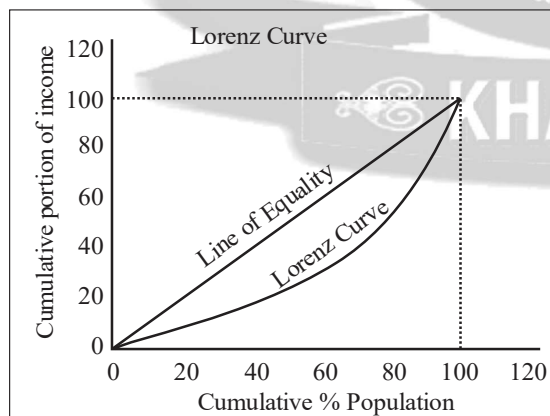


- यह आय में वितरण की विषमता को मापने की सबसे प्रचलित विधि है।
- आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप करता है।

$$\text{गिनी गुणांक} = \frac{\text{छायांकित क्षेत्रफल}}{\text{समता रेखा के नीचे का सम्पूर्ण क्षेत्रफल}}$$

लॉरेंज वक्र विधि

- 1905 में मैक्स ओ. लॉरेंज ने विकसित किया था।
- इस विधि द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात करते हैं।
- इस वक्र का प्रत्येक बिन्दु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के स्तर के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं।



गिनी गुणांक

- 1912 में इटैलियन सांख्यिकीविद् कोराडो गिनी द्वारा विकसित किया था।

- भारत में योजना आयोग द्वारा बनाए गए गरीबी मापन हेतु प्रमुख समितियाँ-

समितियाँ	वर्ष
डॉ. वाई.के. अलघ समिति	1977
लकड़ावाला समिति	1989
सुरेश तेंदुलकर समिति	2005
सी.रंगराजन समिति	2012

बेरोजगारी (Unemployment)

- बेरोजगारी वह आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को समय पर उसके योग्यता अनुसार उचित मूल्य पर रोजगार नहीं मिलता है। बेरोजगारी के कई स्वरूप होते हैं। इससे संबंधित आंकड़े NSSO द्वारा जारी किए जाते हैं।
- बेरोजगारी को दर्शाने के लिए फिलिप्स वक्र का प्रयोग किया जाता है।
- संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment)**
 - जब मांग में परिवर्तन हो और मांग में संरचनात्मक बेरोजगारी की कमी हो जाए तो इससे उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह दीर्घकालीन होता है। अस्फिति (धन की कमी) के कारण यह संचालक या ढाचागत बेरोजगारी उत्पन्न करती है। भारत में सबसे ज्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है।
- चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment)**
 - जब मांग पुरी तरह समाप्त हो जाए अर्थात् समग्र मांग की अभाव में फैक्ट्री बंद जाए तो उससे जुड़े सभी लोग बेरोजगार होते हैं।

- चक्रीय बेरोजगारी मुख्यतः व्यापार चक्र से संबंधित होती है तथा यह अस्थायी प्रकृति की होती है।

Ex :- NOKIA/FACTORY → परिवहन → DEALER Distributer → Wholesaller → Retailer → उपभोक्ता

- घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment)**
 - जब तकनीकी विकास होता है तो पुराने तकनिक के लोग तब तक के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। जब तक कि वो नई तकनिक सिख नहीं जाते हैं। अर्थात् नई नौकरी को खोजने के दौरान हुई बेरोजगारी घर्षणात्मक होती है। यह अल्पकालीन होती है। यह भारत के शहरी क्षेत्र में देखी जाती है।
- छिपी बेरोजगारी/अदृश्य/प्रच्छन्द (Disguised Unemployment)**
 - वह बेरोजगारी जिसमें मजदूर काम पर लगा हुआ तो दिखता है किंतु उसकी उत्पादकता (सिमांत उत्पादकता) शून्य होती है। अर्थात् उसे नौकरी से हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कृषि क्षेत्र में यही बेरोजगारी देखी जाती है।
- मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)**
 - वैसी बेरोजगारी जो किसी खास मौसम में आती है मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है।
- Ex :- फसल कटाई के बाद किसान ठंडी में जुस का कार्य।
- शिक्षित बेरोजगारी (Educational Unemployment)**
 - जब किसी व्यक्ति को उसके योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। इसमें मजदूर अपनी कुल क्षमता से कार्य नहीं करता है।
- Note :- ओकून का नियम (Okun's Law)- यह नियम किसी देश की विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताता है। यह दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है।



KHAN SIR



आर्थिक नियोजन (Economic Planning)

राष्ट्रीय नियोजन (National Planning)

- ☞ संसाधनों के उचित उपयोग के लिए सरकार नियोजन (प्लानिंग) करती है। भारत में नियोजन का इतिहास योजना आयोग से भी पुराना है।
- ☞ भारत में सर्वप्रथम 1934 ई. में एम. विश्वेश्वरैया की पुस्तक *Planned Economy of India* में योजना की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी।
- ☞ यह योजना 10 वर्षीय थी। जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय को दोगुना करना तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना था।
- ☞ इसके पश्चात् 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में पं. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया। इसे 'कांग्रेस योजना' भी कहा जाता है।
- ☞ वर्ष 1944-45 में भारत के आठ प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा भारत के आर्थिक विकास हेतु एक प्लान बनाया गया जिसे 'बांबे प्लान' कहा गया।
- ☞ वर्ष 1944 में श्रीमन् नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी विचारधारा के रूप में गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया। जिसमें कृषि क्षेत्र एवं लघु, कुटीर औद्योगिक विकास पर बल दिया।
- ☞ वर्ष 1945 में एम.एन. राय द्वारा जन योजना को प्रस्तुत किया। जिसमें लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया।
- ☞ वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान भी तैयार किया गया।
- ☞ के.सी. नियोगी ने सोवियत संघ से नियोजन की व्यवस्था ली।
- ☞ इस नियोजन को इन्होंने समवर्ती सूची में रख दिया।
- ☞ और इन्हीं के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया गया।

योजना आयोग (Planning Commission)

- ☞ नियोजन के लिए 15 March, 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया जो रूस के संविधान से लिया गया। योजना आयोग को 1 Jan, 2015 को निति (National Institution for transforming India-NITI) आयोग कर दिया गया।
- **मुख्य कार्य**— पंचवर्षीय योजना बनाना।
- ☞ अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी है।
- ☞ प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे।
- ☞ योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे।

राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council)

- ☞ इसकी स्थापना 6 August, 1952 को हुई। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं एवं केंद्रीय मंत्री परिषद् के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य रहते हैं। यह पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है।

Remark :- योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् दोनों की चर्चा संविधान में नहीं है, अतः यह गैर संविधानिक निकाय है। इन दोनों की रचना संविधान के बाद हुई। अतः इसे संविधानोत्तर निकाय कहते हैं।

Note :- योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहते हैं।

आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य—

1. आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
2. सामाजिक न्याय।
3. पूर्ण रोजगार की प्राप्ति
4. गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन।
5. आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।
6. निवेश एवं पूंजी निर्माण।
7. समान आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी।
8. आधुनिकीकरण
9. मानव संसाधन का विकास
10. निजीकरण उदारीकरण तथा वैश्वीकरण में गरीबों की सुरक्षा।
11. तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास।
12. धारणीय विकास।

नीति आयोग

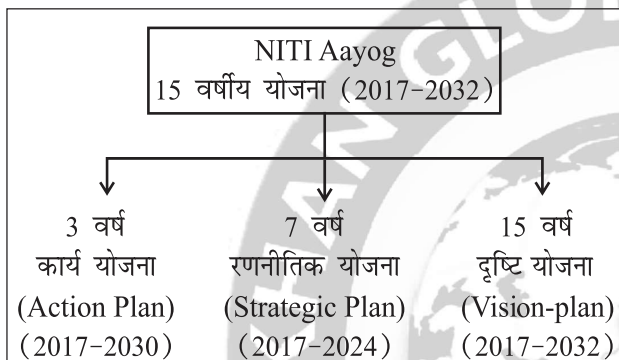
- ☞ राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान (नीति आयोग) की स्थापना एक सरकारी संकल्प द्वारा 1 जनवरी, 2015 को की गई।
- ☞ नीति आयोग भारत सरकार का थ्रिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह केन्द्र एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीतिक एवं तकनीकी सलाह देता है।

➤ नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य

- ☞ आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना।
- ☞ दीर्घकालिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का रूपरेखा तैयार करना।
- ☞ राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास हेतु रणनीतियों को विकसित करना।
- ☞ सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना।

नीति आयोग की संरचना

- **अध्यक्ष**— भारत के पदेन प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी)
- **उपाध्यक्ष**— प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। (सुमन कुमार बेरी)
- **कार्यकारी परिषद**— सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघशासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल।
- **पूर्णकालीन सदस्य**— डॉ. अरविंद बिरमानी, वी.के. सारस्वत, रमेश चंद्र तथा वी.के. पॉल।
- **पदेन सदस्य**— राजनाथ सिंह (रक्षा मंत्री), अमित शाह (गृह मंत्री), निर्मला सीतारमण (वित्त मंत्री)।
- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**— बी.वी. आर सुब्रमण्यम्।



योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर

योजना आयोग	नीति आयोग
यह एक पुरानी संस्था थी।	यह नई एवं आधुनिक संस्था है।
गैर- सांविधिक और असंवैधानिक	गैर- सांविधिक और असंवैधानिक
सचिव	CEO
मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) नहीं होते हैं।	मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) होते हैं।
यह मंत्रालयों एवं राज्य सरकारी कोषों की वितरण करती थी।	कोषों का वितरण नहीं करती है।
Deputy chairman	Vice-chairman
Top-down approach	Bottom-up approach. (सहकारिता संघीय)

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956)

- ☛ यह हेराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि उत्पादन अपने लक्ष्य से दोगुना बढ़ गया।

- ☛ प्रथम योजना में ही भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चालू की गईं।

अन्य प्रमुख उद्देश्य—

- ☛ कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता।
- ☛ देश के विभाजन तथा युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना।
- ☛ न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।
- ☛ लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार तथा औद्योगिकरण हेतु वांछित पृष्ठभूमि तैयार करना।

Note:— योजना के अंतिम दो वर्षों में अच्छे उत्पादन के कारण यह योजना सफल रही।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961)

- ☛ यह P.C. महानलोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग को स्थापित करना था।

Note:— भारी उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशों से अत्यधिक ऋण लेना पड़ा, जिस कारण इस योजना को असफल माना जाता है।

- ☛ भारत के बड़े-बड़े स्टील प्लांट इसी योजना में लगे हैं।
- ☛ इस योजना में राउरकेला (उड़ीसा) जर्मनी के सहयोग से, भिलाई (छत्तीसगढ़) सोवियत संघ के सहयोग से तथा दुर्गापुर (पं. बंगाल) U.K. के सहयोग से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई।

अन्य प्रमुख उद्देश्य—

- ☛ आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष जोर देकर तीव्र औद्योगिकरण करना।
- ☛ रोजगार अवसरों में बड़े पैमाने पर प्रसार।
- ☛ आय और धन की असमानता में कमी करना और आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण करना।
- ☛ झारखण्ड का बोकारो स्टील प्लांट USSR के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-1966)

- ☛ यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः सफूर्त बनाने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुई।
- ☛ इस योजना का उद्देश्य कृषि तथा उद्योग दोनों को बढ़ाना था।
- ☛ खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा उद्योगों और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना।
- ☛ बुनियादी उद्योगों जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली के क्षेत्र का विस्तार तथा मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना ताकि भविष्य में 10 साल के भीतर अपने ही संसाधनों से औद्योगिकरण की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
- ☛ देश की मानवीय शक्ति का पूर्ण प्रयोग एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि।

इस योजना की असफलता के तीन कारण हैं—

- (i) 1962 ई. में चीन से युद्ध जिसके बाद नेहरू की मृत्यु हो गई।
- (ii) 1965 ई. में पाकिस्तान से युद्ध
- (iii) 1966 का भीषण सूखा। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया— जय जवान-जय किसान।

Note :- यह अबतक की सबसे असफल योजना रही है।

- ☞ इस योजना के बाद 3 साल तक कोई योजना नहीं बनी जिसे योजना अवकाश कहते हैं।

योजना अवकाश (Plan Holidays)

- ☞ वर्ष 1966 से 1969 के बीच चौथी योजना के प्रारूप के तहत ही तीन वार्षिक योजनाएं बनायी गई।
- ☞ वर्ष 1965 में भारत-पाक युद्ध, लगातार दो वर्षों का घोर सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन, आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा योजना के लिए संसाधनों में कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने में देरी हुई।

➤ हरित क्रांति

- ☞ यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में 1966 ई. में प्रारंभ हुई।
- ☞ विश्व में इसका जनक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलंग को मानते हैं।
- ☞ भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामी नाथन हैं। हरितक्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था।
- ☞ हरित क्रांति में उन्नत बीज High yield variety के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया।
- ☞ हरित क्रांति में मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसमें गेहूँ का उत्पादन बढ़ गया, जबकि धान के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन वहीं दलहन एवं तिलहन का उत्पादन घट गया।
- ☞ हरित क्रांति का केन्द्र UP के शामली में था तथा इससे सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ।

➤ द्वितीय हरित क्रांति

- ☞ इसमें अनुवांशिक रूप से वृद्धि किये गए फसल को बोते हैं। ऐसे फसलों को जेनेटेकिली मोडीफाई (G.M.) फसल कहते हैं।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)

- ☞ इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी. आरगाडगिल ने तैयार किया है। मई, 1970 ई. में संसद में रखा।
- ☞ इस योजना का मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था, किंतु यह योजना अस्थिर हो गई क्योंकि, इस दौरान प्रतिकूल मौसम से फसल बर्बाद हो गई।
- ☞ इसी योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।
- ☞ परिवार नियोजन इस योजना का मुख्य लक्ष्यों में से एक था।
- ☞ ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति इसी योजना के समय में प्रारंभ की गयी थी।

अन्य प्रमुख उद्देश्य—

- ☞ राष्ट्रीय आय एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि।
- ☞ आय एवं सम्पत्ति का समान वितरण तथा क्षेत्रीय असमानता में कमी करना।
- ☞ संतुलित विकास पर जोर देना।
- ☞ तीव्र गति से औद्योगिक विकास तथा आधारभूत एवं भारी उद्योग पर विशेष बल।

Note :- उड़ीसा में भीषण चक्रवात आ गए, 1971 ई. में बंगलादेश युद्ध हो गया तथा शरणार्थी का संकट आ गया। जिस कारण यह योजना असफल हो गई।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78)

- ☞ इस योजना में पहली बार 'गरीबी हटाओ' का नारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा दिया।
- ☞ इस योजना के दो प्रमुख उद्देश्य 'गरीब हटाओ' तथा 'आत्मनिर्भरता की प्राप्ति' थी।
- ☞ गरीबी हटाने के लिए वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया तथा इसी वर्ष 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई।
- ☞ 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' इसी योजना में प्रारंभ की गई।
- ☞ इस योजना को जनता पार्टी की सरकार ने समय से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया और इसके स्थान पर अनवरत योजना लाया गया।
- ☞ इस योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा न्यायपूर्ण श्रम शक्ति के विकास को महत्व दिया गया।
- **अनवरत योजना [Rolling Plan (1978-80)]**
- ☞ अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक "एशियन ड्रामा" में किया था, जिसे जनता पार्टी की सरकार ने लाया।
- ☞ यह गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को DDT लकड़ावाला ने तैयार किया।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)

- ☞ इस योजना में औद्योगीकरण के साथ-साथ गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया।
- ☞ जनता पार्टी की सरकार द्वारा पांचवी योजना को समय से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर छठी योजना (1978-83) लायी परंतु इस दौरान जनता पार्टी की सरकार गिर गई और कांग्रेस पार्टी पुनः (1980 में) सत्ता में आई तो छठी योजना को पुनः व्यवस्थित कर 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1985 तक के लिए लागू किया।
- ☞ इसी दौरान 'मानक व्यक्ति वर्ष' को रोजगार मापने के लिए अपनाया गया।
- ☞ यह योजना अगत-निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसी योजना में एक कार्यदल ने 'गरीबी निर्देशांक' तैयार किया तथा गरीबी रेखा से ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया।

- छठी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई।
- अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को पहली बार छठी योजना में अपनाया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)

- इसे डॉ. चक्रवर्ति ने तैयार किया। इसमें गरीबी को परिभाषित किया गया।
- यह योजना दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल देने वाली थी।
- इस योजना का लक्ष्य अनाज के उत्पादन तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय की मूलभूत अवधारणाओं के तहत विकास करना था। 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया।

Note :- यह एक सफल योजना रही।

अन्य प्रमुख उद्देश्य-

- खाद्यान्न के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- एक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करना।
- ऊर्जा संरक्षण एवं गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास।
- **योजना अवकाश (1990-1992)**
- इस समय राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। जिसमें अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने पर बल दिया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)

- यह योजना दो वर्ष की देरी से शुरू हुई क्योंकि 1991 में आर्थिक संकट था।
- इस योजना को मनमोहन सिंह ने तैयार किया।
- इस योजना में मानव संसाधन, शिक्षा तथा उदारीकरण पर जोर दिया गया। जिस कारण इसे शिक्षा में समर्पित योजना कहते हैं।
- यह योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत 'जॉन डबल्यू मुलर' मॉडल पर आधारित थी।

अन्य प्रमुख उद्देश्य-

- शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजित करना।
- प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक विकास।
- पेयजल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का विकास।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)

- यह अमरसेन मॉडल पर आधारित थी इसमें न्याय पूर्ण वितरण प्रणाली को अपनाया गया।
- 'सामाजिक न्याय का समता' के साथ आर्थिक विकास नौवीं पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य था।
- इस योजना का लक्ष्य राजकोषीय नीति लागू करना था ताकि केन्द्र, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र में राजस्व घाटे को कम किया जा सके।

Note:- यह योजना भूकम्प, कारगिल युद्ध तथा 1996 के परमाणु परीक्षण के कारण असफल हो गई।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007)

- अधिक व्यापक आगत-निर्गत मॉडल पर आधारित दसवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2007) ऐसे समय लागू की गई जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का दौर अपनी चरम पर था।
- इसमें शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्वशिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया।
- इस योजना में कृषि को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र के विकास में लाभ को व्यापक रूप से फैलाने की सर्वाधिक शक्ति है।
- इस योजना में उन क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित किया गया जो लाभप्रद रोजगार के अवसर सृजित करने वाले थे।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)

- इसमें हर क्षेत्र के विकास के लिए सामावेशी विकास चलाया गया।
- इस योजना में तीव्रतम विकास पर जोर दिया गया।
- इसी योजना के दौरान 1 अप्रैल, 2010 को मिड-डे-मिल योजना प्रारंभ की गई हालांकि इस योजना को संसद ने 2005 में मंजूरी दी थी।
- इस योजना में वन क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया किंतु वन 24% से घट कर 22% रह गया।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017)

- इसमें प्रशासनिक सुधार तथा भ्रष्टाचार में कमी का लक्ष्य रखा गया किंतु यह दोनों बढ़ गया। इस योजना में परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया।
- तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास इस योजना का उपशीर्षक है।
- यह योजना ऐसे समय में शुरू हुई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था वित्तीय संकट का सामना कर रही थी जो 11वीं योजना के अंतिम वर्ष में यूरोपीय जोन पर आए ऋण संकट के कारण शुरू हुआ। इस वित्तीय संकट का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ा।
- इस योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमारी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था की विकास दर को फिर से तीव्र किया जाए और साथ में यह भी सुनिश्चित हो कि हमारी विकास प्रक्रियाएं समावेशी एवं धारणीय रहे।

□□□

- ☞ किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के आगामी वर्ष के आय और व्यय के व्यौरे को बजट कहते हैं।
 - ☞ बजट फ्रेंच भाषा के बुजेट (Bougeut) शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है **चमड़ा का थैला**।
 - ☞ 1773 ई० में ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री राबर्ट वालपोल ने पार्लियामेंट में वित्तीय प्रस्ताव पेश करने हेतु एक चमड़े के थैला खोलकर उससे संबंधित कागजात निकाला तो संसद सदस्यों ने मजाक में इसे जादू के थैले के अर्थ में बजट खुल गया, बजट खुल गया कहा। इसके बाद वार्षिक आय-व्यय के प्रस्ताव के लिए बजट शब्द का प्रयोग होने लगा।
 - ☞ भारत का पहला बजट लार्ड कैनिंग के समय 7 अप्रैल, 1860 को तत्कालीन वित्तमंत्री जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कहा जाता है।
 - ☞ स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवम्बर, 1947 को पहले वित्त मंत्री R.K. सन्मुखम् सेट्टी द्वारा पेश किया गया था।
 - ☞ गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 जॉन मेथाई ने पेश किया।
- भारत के तीन प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किए—**
1. जवाहरलाल नेहरू
 2. इंदिरा गांधी
 3. राजीव गांधी।
- ☞ भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी, जबकि पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं।
 - ☞ सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने का श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है। इन्होंने 10 बार (8 बार नियमित, 2 बार अंतरिम) बजट प्रस्तुत किए।
 - ☞ प्रारम्भ में रेल बजट एवं आम बजट एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता था लेकिन 1924 ई० में एकवर्ध समिति के सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया तथा 2016 में पुनः रेल बजट एवं आम बजट को मिला दिया गया।
 - ☞ भारत में बजट प्रस्तुत 2017 से 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है।
 - ☞ बजट को तैयार कराने का काम प्राक्कलन समिति करती है।
 - ☞ बजट का टीवी पर प्रसारण 1992 से प्रारम्भ हुआ।
 - ☞ बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है किन्तु वे वित्तमंत्री से प्रस्तुत करवाते हैं।
 - ☞ बजट प्रस्तुत करने की चर्चा संविधान में नहीं है बल्कि इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है। एक वर्ष के केन्द्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण [Annual Financial Statement (AFS)] कहा जाता है।
 - **अनु० 112**
 - ☞ इसमें बजट के तहत वित्तमंत्री भिन्न-भिन्न कार्य के योजना को प्रस्तुत करते हैं।
 - **अनु० 113**
 - ☞ इनमें प्राक्कलन के तहत खर्च का विवरण दिया जाता है।
 - **अनु० 114**
 - ☞ विनियोग विधायक के तहत धन निकालने का प्रस्ताव रखा जाता है। जबतक विनियोग विधायक पारित नहीं हो जाता है तबतक संसद से धन नहीं निकाला जा सकता है। इसी कारण संसद को राष्ट्रीय धन (कोष) का रक्षक कहते हैं।
 - **अनु० 115**
 - ☞ इसमें अतिरिक्त अनुदान के तहत प्राक्कलन द्वारा दिए गए पैसे घट जाने पर पैसा निकाला जाता है।
 - **अनु० 116**
 - ☞ इसमें लेखानुदान के द्वारा अग्रिम राशि निकाल ली जाती है।

बजट के प्रकार

1. शून्य आधारित बजट

- ☞ जब बजट में पिछला लेन-देन को छोड़कर एकदम नए सिरे से बजट बनाया जाता है तो उसे शून्य आधारित बजट कहते हैं।
- ☞ भारत में शून्य आधारित बजट 1987-88 ई. में राजीव गांधी ने लाया तथा विश्व में शून्य आधारित का प्रथम प्रयोग 1977 ई. में अमेरिका के जिमी कार्स्टर ने किया।
- ☞ शून्य आधारित बजट के जनक अमेरिका के पिटर फायर थे। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम आंध्रप्रदेश में अपनाया गया।

2. जेन्डर बजट

- ☞ जिस बजट में स्त्री पुरुष के लिए अलग से कुछ प्रावधान हो जेन्डर बजट कहलाता है।
- ☞ 2001 में महिला शक्तिकरण के बाद जेन्डर बजट को अधिक बढ़ावा दिया गया।
- ☞ इसका सबसे पहला प्रयोग 1982 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था।

3. संतुलित बजट

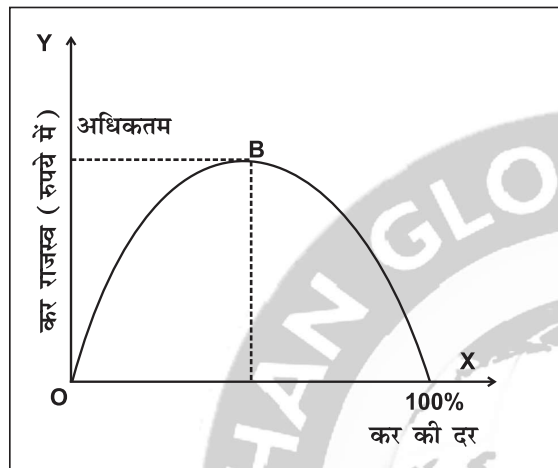
- ☞ वैसे बजट जिसमें आय तथा व्यय बराबर हो संतुलित बजट कहलाता है।

4. आउट कम बजट

- जब सरकार पैसा को खर्च करती है उस धन द्वारा किए गए कार्य का रिपोर्ट कार्ड (प्रगति) को आउटकम बजट कहते हैं।
- इस बजट की शुरुआत श्री पी.चिदम्बरम ने 2005 ई. में किया।

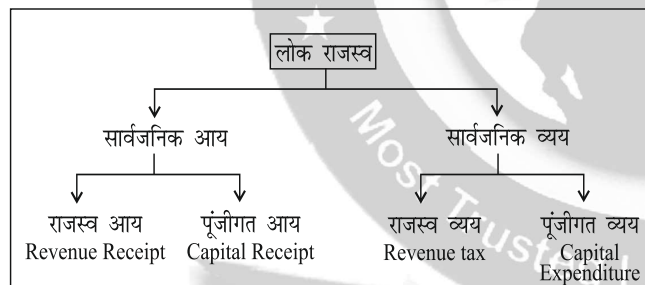
➤ लैफर वक्र (Laffer Curve)

- इसका प्रतिपादन अमेरिकी अर्थशास्त्री ऑथर लैफर द्वारा किया गया जो कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के बीच संबंध को दर्शाता है।



लोक राजस्व (Public Finance)

- सरकारी लेनदेन को लोक राजस्व कहते हैं।



➤ सार्वजनिक आय (Public Revenue)

- सरकार के कुल आय को सार्वजनिक आय कहते हैं।

यह दो प्रकार का होता है—

1. राजस्व आय

- वैसा आय जिसे सरकार लौटाती नहीं है, राजस्व आय कहलाता है अर्थात् इसपर सरकार की देनदारी (ऋणभार) शून्य रहता है।
- केन्द्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है जबकि राज्य सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बिक्री कर है।

2. पूंजीगत आय

- सरकार का वैसा धन जिसे सरकार को लौटाना पड़े अर्थात् जिसपर सरकार की देनदारी रहती है।

Ex. :- बैंक तथा बॉन्डपेपर के रूप में जमा धन।

Remark :- सरकार अपने पूंजीगत आय को बनाए रखने के लिए cashless पर विशेष जोर दे रही है।

➤ सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)

- सरकार के कुल व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं।

यह दो प्रकार का होता है—

1. पूंजीगत व्यय

- यह एक वर्ष में प्रारम्भ होकर कई वर्षों तक धीरे-धीरे होता रहता है यह बहुत बड़ा व्यय होता है इसके द्वारा ढाँचागत विकास होता है।

Ex. :- सड़क, पुल, Airport।

2. राजस्व व्यय

- यह व्यय अल्पकालीन तथा छोटा होता है, जिस वर्ष यह प्रारम्भ होता है उसी वर्ष समाप्त हो जाता है।

Ex. :- सहायता राशि, सब्सिडी, etc.

➤ घाटा (Deficite)

- जब व्यय आय से अधिक हो जाए तो उसे घाटा कहते हैं। घाटा कई प्रकार का होता है।

1. राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व आय

2. पूंजीगत घाटा = पूंजीगत व्यय – पूंजीगत आय

3. सार्वजनिक घाटा = सार्वजनिक व्यय – सार्वजनिक आय

सार्वजनिक घाटा = पूंजीगत घाटा + राजस्व घाटा

Note :- सार्वजनिक घाटा को बजट घाटा कहते हैं।

➤ राजकोष घाटा (Fiscal Deficite)

- जब बजट घाटा में ऋणभार को जोड़ देते हैं तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं।

Note :- राजकोषीय घाटा सबसे प्रमुख घाटा है। जिस देश का राजकोषीय घाटा जितना अधिक होगा, उस देश की प्रगति में उतनी अधिक बाधा आएगी।

➤ प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)

- राजकोषीय घाटा में ब्याज घटाने पर प्राप्त घाटा को प्राथमिक घाटा कहते हैं।

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान

राजकोषीय घाटा = प्राथमिक घाटा + ब्याज भुगतान

➤ मौद्रिक घाटा (Monetary Deficit)

- नए नोट को छपने पर आए खर्च करने के कारण लगने वाला घाटा, मौद्रिक घाटा कहलाता है। यह तभी होगा जब सरकार अत्यधिक नोट छापे या नोट बदल दें।

➤ योजनागत व्यय

- वैसा व्यय जिसका अनुमान पहले से ही लगाया जा चुके हो उसे योजनागत व्यय कहते हैं।

Ex. :- वेतन, विकासात्मक परियोजनाएं।

➤ गैर योजनागत व्यय

- वैसा व्यय जिसका पूर्व अनुमान सरकार को न हो, गैर योजनागत व्यय कहलाता है।

Ex. :- सहायता राशि, सब्सिडी, रक्षा व्यय।

- यह एक अनिवार्य भुगतान है जिसे कानूनी रूप से देना ही पड़ता है। कर उतना ही निश्चित है जितना की मृत्यु क्योंकि यह सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है। कराधान का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था।

- यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
- इसकी निगरानी के लिए PAN CARD (Permanent Account Number) दिया जाता है।

वर्तमान (Financial Year 2024) में Income Tax के 6 Slab है-

Tax के प्रकार

1. प्रगतिशील कर (Progressive Tax)

- यह आय के बढ़ने से बढ़ता जाता है और इसका प्रभाव अमीर पर ज्यादा पड़ता है। यह आय एवं सम्पत्ति के असमानता को दूर करता है।

2. प्रतिगामी कर (Regressive Tax)

- यह कम आय वालों पर अधिक Tax लगता है। यह गरीबों को अधिक प्रभावित करता है।

3. समानुपाती (Proportional)

- वैसा कर जो आय के घटने या बढ़ने से बदलता नहीं है समानुपाती कर कहलाता है। यह गरीब तथा अमीर को समान रूप से प्रभावित करता है।

4. अधोगामी कर (Degressive Tax)

- यह कर आय के बढ़ने से प्रारम्भ में बढ़ता है। किंतु एक निश्चित सीमा पर जाकर एक समान हो जाता है। इसमें प्रारंभ में प्रगतिशील के गुण होते हैं। बाद में समानुपाती के गुण होते हैं।

- इसमें सरकार बिना कुछ दिए धन ले लेती है।

➤ शुल्क (Fee)

- इसमें सरकार कुछ देने के बाद धन लेती है।

➤ करापात (Incidence of Tax)

- जिस व्यक्ति पर tax लगाया जाता है, उसे करापात कहते हैं।

➤ कराघात (Impact of Tax)

- जो व्यक्ति Tax की धन राशि देता है। उसे कराघात कहते हैं।

Income Tax Slab	
0 – 3 लाख	No Tax
3 – 6 लाख	5%
6 – 9 लाख	10%
9 – 12 लाख	15%
12 – 15 लाख	20%
15 लाख ↑	30%

- Income का ब्योरा देने के लिए कम्प्यूटेशन बनना पड़ता है। कम्प्यूटेशन (Computation) के इनकम के आधार पर ही Income Tax ITR जमा करना होता है।

➤ उपकर (Cess)

- Tax के अतिरिक्त लगाया गया कर शेष कहलाता है। शेष की धनराशि के द्वारा सरकार प्रौढ़ शिक्षा सफाई, सामाजिक सुरक्षा, इत्यादि पर खर्च करती है।

- यह Tax के अतिरिक्त अलग से Tax लिया जाता है। जिसे Tax On Tax कहते हैं। इसे 4% तक लिया जाता है। Cess का पूरा पैसा केन्द्र सरकार के पास रहता है।

➤ अधिभार (Sur Charge)

- यह भी Tax पर ही लिया जाता है। इसे भी Tax On Tax कहते हैं। यह तब लिया जाता है जब कोई व्यक्ति 50 लाख से अधिक देता है। यह 10% तक लिया जाता है।

➤ संपत्ति कर (Wealth Tax)

- संपत्ति से अर्जित किए गए लाभ पर लगने वाले कर को संपत्ति कर कहते हैं।

- यह राज्य सरकार का कर है।

➤ निगम कर (Corporate Tax)

- यह बड़े-बड़े कम्पनी पर लगाया जाता है। यह प्रत्यक्ष कर है। यह मुनाफे के 30% पर लगाया जाता है। केन्द्र सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है।

Ex. :- Tata, बिरला, Reliance

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

- वैसा कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, अन्ततः उसी से वसूल भी किया जाता है, Direct Tax कहलाता है।

Ex. :- आयकर, सम्पत्ति कर, निगम कर, उपहार कर, धन कर, कृषि कर आदि।

➤ आयकर (Income Tax)

- यह कर सीधे करदाता की भुगतान करने की क्षमता से संबंधित होता है। जिसे प्रत्येक वर्ष करदाता को अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा केन्द्र सरकार को आयकर के रूप में देना होता है।

➤ उपहार कर (Gift Tax)

- यह प्रत्यक्ष कर है। जब 50 हजार से अधिक का Gift मिलता है, तो यह Tax लगाया जाता है। यह 30% होता है।

Ex. :- K.B.C. में विजेता को 5 करोड़ में 3.5 करोड़ रुपये मिलते हैं।

Note :- विवाह में समधी द्वारा दिए गए उपहार पर यह Tax नहीं लगता है।

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)

- यह जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति उसका भुगतान नहीं करता बल्कि दूसरा व्यक्ति उसका भुगतान करता है। यह वस्तुओं पर लगाया जाता है। जैसे बिक्री कर, सीमा शुल्क, वाहन कर।

➤ सीमा शुल्क (Custom Duty)

- यह कर देश के सीमा से बाहर जाने वाली तथा देश में बाहर से आनेवाली वस्तुओं पर लगता है।
- इस कर को केंद्र सरकार द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है जबकि वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र एवं राज्य के बीच बांटा जाता है।

➤ उत्पाद शुल्क (Excise Duty)

- यह कर केंद्र सरकार द्वारा किसी देश के भीतर वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है।
- मादक पेय पदार्थ जैसे शराब, तंबाकू, गांजा आदि पर राज्य सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क लगाया जाता है किंतु तंबाकू से निर्मित वस्तु जैसे सिगरेट पर केंद्र सरकार कर लगाती है।
- स्थानीय सरकार के कारण इसे पंचायत एवं नगरपालिका के लोग लेते हैं।

Ex. :- मालगुजारी, भवन कर, खेती कर, चुंगीकर।

➤ VAT (Value Added Tax)

- इसको सबसे पहले फ्रांस ने अपनाया था। भारत में इसे L.K. झा समिति के सिफारिश पर लागू किया गया। यह अप्रत्यक्ष कर है। इसे बिक्री पर राज्य सरकार लेती थी।

Note :- (Central Value Added Tax (CENVET) केंद्र सरकार उत्पादन पर लेती थी। Cenvet अप्रत्यक्ष कर था। Vet Tax को सबसे पहले 2005 में हरियाणा ने माना था जबकि सबसे अंत 2008 U.P. ने माना।

➤ सेवाकर (Service Tax)

- यह राज्य सरकार लेती थी। इसे 1994-95 में लाया गया।

Note :- वर्तमान में Vat तथा Service Tax को समाप्त करके GST लाया गया है।

- वर्ष 2003 में 88वां संविधान संशोधन द्वारा इस कर को केंद्र सूची में डाल दिया गया।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) (Goods and Service Tax)

- यह एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत का GST कनाडा मॉडल पर आधारित है। विश्व में सबसे ज्यादा GST की दर भारत में है। GST चोरी करने वाले को 5 साल जेल का प्रावधान होगा।
- GST पंजीकरण करने पर 15 अक्षर का पंजीकरण नम्बर दिया जाता है।

GST – Identification Number

10 –	<u>PYKAZ6318K</u>	<u>IPQ</u>
State	PAN No.	Business

- GST के दायरे में 20 लाख से अधिक टर्न ओवर वाले व्यापारी को रखा गया है।
- GST के सभी निर्णय GST परिषद् लेती है।
- GST परिषद् में 33 सदस्य होते हैं।

- वित्तमंत्री = 1 अध्यक्ष
- राज्यमंत्री = 1
- राज्य के वित्तमंत्री = 28
- UT के वित्तमंत्री (दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मूकश्मीर) = 3

Note :- GST परिषद् के अध्यक्ष वित्तमंत्री होते हैं। भारत में GST अरविन्द समिति के सिफारिश पर लागू किया गया। GST लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया।

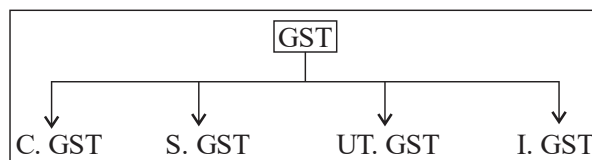
- GST की चर्चा अनु. 379 में है।
- IGST की चर्चा अनु. 369 में है।
- भारत की GST VAT को हटाकर लाया गया है।
- भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है।
- GST लागू करने वाले पहला राज्य असम था।
- GST आने से सेवा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया।

- GST Monthly भरा जाता है।
- GST प्रत्येक महीना के 24 तारीख को भर देना होता है।

भारत में GST के चार Class बनाये गये हैं-

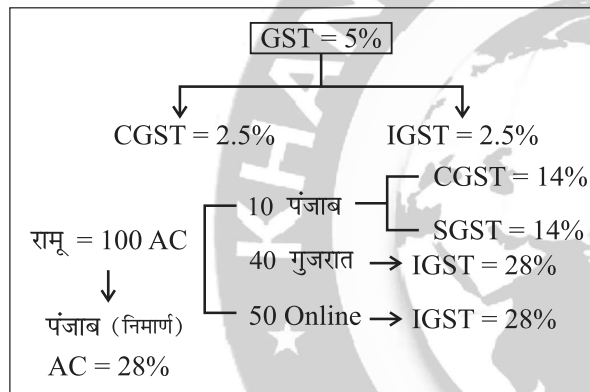
- 5% – इसमें आवश्यक वस्तु को रखा गया है।
- 12 % – इसमें उपयोगी वस्तु को रखा गया है।
- 18% – इसमें आरामदायक वस्तु को रखा गया है।
- 28% – इसमें विलास्तापूर्ण वस्तुओं को रखा गया है।

GST को चार श्रेणी में बाँटा गया है-



- **Central GST (C.GST)**
 - ☞ यह केन्द्र सरकार लेती है यह वस्तु के उत्पादन पर लगता है।
- **State GST (S.GST)**
 - ☞ जिस राज्य में वस्तु बनी है, यदि उसी राज्य में बेची जाय तो SGST लगता है।
- **Union Territory GST (UT.GST)**
 - ☞ यह केन्द्रशासित प्रदेश में बनी वस्तु केन्द्रशासित प्रदेश में ही बिकती है। उसे UT. GST कहते हैं।
- **Integrated GST (I.GST)**
 - ☞ यदि किसी राज्य में बनी वस्तु दूसरे राज्य में बेची जाती है जिस राज्य में उसे बेचा जाता है। वह राज्य IGST लेता है।
 - ☞ Online की सभी खरीदारी IGST के अंतर्गत आता है।

Note :- चार प्रकार के GST में से C.GST अनिवार्य रूप से देना ही है। शेष तीन GST में से कोई एक GST लगेगा।



महत्वपूर्ण कर सुधार समिति

समितियां	कार्य क्षेत्र
राजा चेलैया समिति	कर सुधार
वाँचू समिति	प्रत्यक्ष कर
केलकर समिति	प्रत्यक्ष कर
एल.के. झा समिति	अप्रत्यक्ष कर
रेखा समिति	अप्रत्यक्ष कर
भुरेलाल समिति	मोटरवाहन में कर वृद्धि
रंगराजन समिति	पेट्रोलियम उत्पाद पर कर
वाई.वी. रेड्डी	आयकर में छूट

प्रत्यक्षकर (Direct Tax)	अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
सम्पत्ति कर (Assets Tax)	उत्पादन कर (Excise Tax)
कृषि कर (Agriculture Tax)	सेवा कर (Service Tax)
धन कर (Wealth Tax)	सीमा कर (Custom Tax)
आय कर (Income Tax)	बाजार कर (Market Tax)
निगम कर (Corporate Tax)	बिक्री कर (Sales Tax)
व्यवसाय कर (Business Tax)	मनोरंजन कर (Entertainment Tax)
भू-राजस्व कर (Land Revenue Tax)	प्रोफेशनल कर (Professional Tax)
मृत्यु कर (Death Tax)	टोल कर (Toll Tax)
उपहार कर (Gift Tax)	स्टाम्प कर (Stamp Tax)

विभिन्न सरकार द्वारा लगाए गए प्रमुख कर

केन्द्रीय कर (Central Tax)	राज्य कर (State Tax)	स्थानीय कर (Local Tax)
सीमा शुल्क (Custom Duty)	कृषि कर (Agriculture Tax)	गृह कर (House Tax)
आय कर (Income Tax)	राजस्व कर (Land Revenue)	चुंगी कर (Toll Tax)
सेवा कर (Service Tax)	स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty)	कृषि भूमि पर कर
केन्द्रीय उत्पाद कर (Central Excise Duty)	राज्य उत्पाद कर (State Excise Duty)	गाँव के हाट / मेला पर कर (मनोरंजन कर)

□□□

08.

व्यापार संतुलन (Trade Balance)

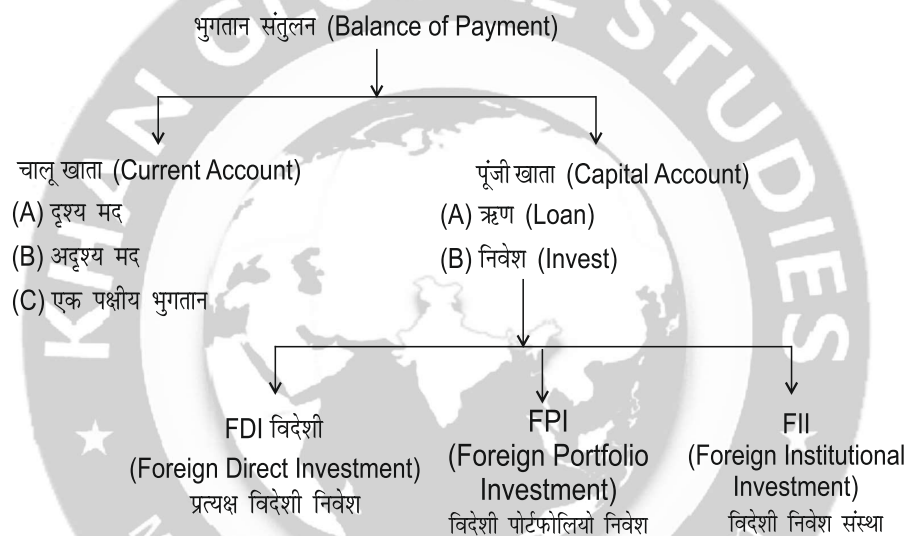
☞ कई देशों के बीच जब व्यापार होता है, तो आयात-निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। यदि यह धनात्मक है तो देश के लिए अच्छा होता है।

Q. भारत चीन को 18 अरब डॉलर (वार्षिक) का निर्यात करता है। जब कि चीन से 72 अरब डॉलर का आयात करता है। तो भारत का व्यापार संतुलन ज्ञात करें।

निर्यात – आयात

$18 - 72 = 54$ अरब डॉलर (ऋणात्मक व्यापार संतुलन)

भुगतान संतुलन (Balance of Payment)



चालू खाता (Current Account)

☞ यह दृश्यमान (दृश्य मद) और अदृश्यमान (अदृश्यमद) वस्तुओं के आयात-निर्यात को दर्शाता है।

- A. **दृश्यमद (Visual Item):**— इसमें सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं (Goods) का आयात एवं निर्यात सम्मिलित होता है।
- B. **अदृश्य मद (Invisible Item) :**— इसमें विभिन्न देशों के बीच होने वाली सेवाओं (Services) शामिल होते हैं।
- C. **एक पक्षीय भुगतान :-** इसमें किसी स्रोत से प्राप्त अनुदान व उपहार (Gift) को शामिल किया जाता है।

का कोई भी Branch लगाती है तो उसे FDI कहते हैं।

➤ **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI (Foreign Portfolio Investment)**

☞ जब कोई विदेशी कम्पनी भारत में 10% से कम निवेश करती है तो उसे FPI कहते हैं।

➤ **विदेशी निवेश संस्था FII (Foreign Institutional Investment)**

☞ वैसी संस्था तथा Bank जो FDI तथा FPI में मदद करते हैं उसे FII कहते हैं।

पूंजी खाता (Capital Account)

☞ यह मुख्य रूप से किसी देश द्वारा एक वर्ष के दौरान विदेशी संपत्तियों और देनदारियों के व्यापार से संबंधित है।

☞ विदेशी निवेश तथा ऋण इसके मुख्य घटक हैं।

➤ **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI (Foreign Direct Investment)**

☞ जब कोई विदेशी कम्पनी या संस्था भारत में किसी कम्पनी की 10% से अधिक की हिस्सेदारी खरीद लेती है और अपने कम्पनी

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया RBI (RESERVE BANK OF INDIA)

☞ इसका गठन 1934 में गठित समिति हिल्टन यंग के सिफारिश पर 1 April, 1935 को किया गया। हिल्टन यंग आयोग ने इसे केन्द्रीय बैंक का दर्जा दिया। इसके पहले अध्यक्ष ओसबर्न स्मिथ थे तथा इसके पहले भारतीय अध्यक्ष C.D देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं।

- ☞ RBI की स्थापना 100, 100 के 5 लाख शेयर को मिलाकर हुई थी किन्तु 1 January, 1949 को सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया।

इसका मुख्यालय मुम्बई है जबकि चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं—
Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkatta.

- ☞ इसका विदेश में कार्यालय लंदन में है। RBI प्रत्येक राज्य के वित्तीय लेनदेन को देखती है। किंतु जम्मूकश्मीर के लेनदेन को SBI देखती है।
- ☞ RBI का लेखा वर्ष 1 July से 30 जून तक होता है। RBI के कार्यों का संचालन 21 सदस्यों वाले बोर्ड सदस्य द्वारा होता है।
1 = गवर्नर
4 = Deputy गवर्नर
4 = क्षेत्रीय ब्रांच के गवर्नर (अध्यक्ष)
2 = वित्त मंत्रालय के अधिकारी
10 = अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार

➤ **RBI के कार्य**

- सरकारी बैंक के रूप में कार्य।
- अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना।
- आर्थिक आकरे जारी करना।
- मुद्रा का विनिमय (Exchange)
- बैंकों पर नियंत्रण रखना।
- साख नियंत्रण
- नोट का निर्गमन
- विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण

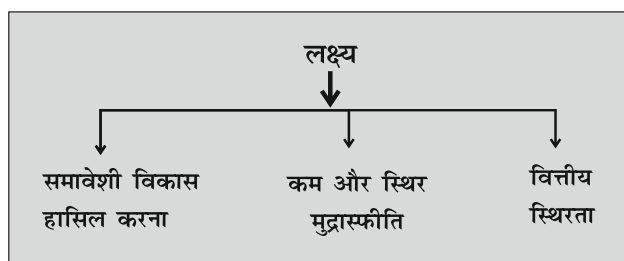
➤ **साख नियंत्रण (Greadit Control)**

- ☞ बाजार की तरलता को नियंत्रित करना साख नियंत्रण कहलाता है। इसके लिए RBI मौद्रिक नीति को अपनाती है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत M.S.F, Reporate, Bank Rate, CRR, SLR, खुले बाजार की नीति (प्रतिभूति की बिक्री) आदि आते हैं।
- ☞ RBI का कार्य साख सृजन करना नहीं होता है बल्कि साख नियंत्रण होता है।
- ☞ साख सृजन का कार्य व्यापारिक बैंक करते हैं।

➤ **मौद्रिक नीति (Monetary Policy)**

- ☞ अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति एवं ब्याज दर को प्रभावित करने वाले नीतियां को ही मौद्रिक नीति कहा जाता है।
- ☞ इसका संचालन केंद्रीय बैंक अर्थात् RBI करता है।
- ☞ इस नीति की घोषणा एक वित्तीय वर्ष में 2014 के बाद 6 बार अर्थात् द्विमासिक की जाती है।

➤ **मौद्रिक नीति के लक्ष्य**



➤ **बैंक दर (Bank Rate)**

- ☞ RBI Bank को 14 दिन से अधिक के लिए (दीर्घकालिक) जिस ब्याज दर पर ऋण देती है उसे Bank Rate कहते हैं।
 $MSF > Reporate > Bank\ rate$

- ☞ अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को बढ़ाया जाता है। जबकि मुद्रा अवस्फीति का सामना करने के लिए बैंक दर को कम किया जाता है।

➤ **रेपो दर (Repo Rate)**

- ☞ RBI बैंकों को 2 से 14 दिन के लिए जिस दर पर ऋण देती है उसे Repo Rate कहते हैं। यह लगभग 4% तक है।
- ☞ इसका प्रयोग RBI के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि के लिए किया जाता है।

➤ **सीमांत स्थायी सुविधा [MSF (Marginal Standing Facility)]**

- ☞ RBI बैंकों को एक दिन के लिए जिस ब्याज दर पर ऋण देती है उसे MSF कहते हैं।

➤ **रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)**

- ☞ जब बैंक अपना अतिरिक्त धन RBI के पास रखते हैं, तो RBI द्वारा दिया गया ब्याज दर Reverse Reporate कहलाता है।

➤ **नगद आरक्षित अनुपात CRR (Cash Reserve Ratio)**

- ☞ बैंकों को अपने कुल जमा का 4% RBI के पास रखना होता है। जिस पर RBI कोई भी ब्याज नहीं देती है। इसे ही नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं।

- ☞ अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए इसमें समय-समय पर परिवर्तन किया जाता है।

- ☞ अत्यधिक मुद्रा स्फीति के समय RBI नगद आरक्षित अनुपात CRR को बढ़ा देता है।

➤ **वैधानिक तरलता अनुपात SLR (Statutory liquidity Ratio)**

- ☞ बैंक को अपने कुल जमा का 18% पैसा अपने पास रखना पड़ता है जिसे SLR कहते हैं।

➤ **PLR (Prime Lending Rate)**

- ☞ बैंक ग्राहकों को जिस दर पर ब्याज देती है उसे PLR कहते हैं।

➤ **Base Rate**

- ☞ बैंक अपने चुनिंदा ग्राहक को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण देती है। Base Rate कहते हैं।

➤ **तरलता (Liquidity)**

- ☞ नगद पैसा को तरलता कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था के लिए सबसे घातक होता है।

➤ **मुद्रास्फीति (Inflation)**

- ☞ तरलता के बढ़ जाने से मुद्रा स्फीति बढ़ जाती है। जिससे महंगाई बढ़ जाती है।

$$\text{तरलता} \propto \text{स्फीति} \propto \text{महंगाई}$$

$$\text{Repo, CRR, SLR} \propto \frac{1}{\text{तरलता}}$$

➤ NEER (Normalise effective exchange rate)

- इसका निर्धारण IMF करती है।
- इसके द्वारा एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा से तुलना किया जाता है। Dollar का NEER 75 भारतीय रुपया होता है। NEER का संबंध बैंकिंग से नहीं है।

➤ खुले बाजार की नीति

- प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री खुले बाजार की नीति कहलाती है। यह मौद्रिक नीति का ही हिस्सा है। इसके अंतर्गत Bond Paper, LIC आदि को रखते हैं। जब सरकार प्रतिभूतियों को बेचती है तो तरलता घट जाती है।
- कालाधन के अधिकता से मौद्रिक नीतियाँ अधिक प्रभावित हो पाती है। इसी कारण मोदीजी ने नोट बदल दिया।
- कालाधन को समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं।

मुद्रा-स्फीति (Inflation)

- मुद्रा का अत्यधिक बढ़ जाना मुद्रा स्फीति कहलाता है। मुद्रा स्फीति के कारण महंगाई बढ़ जाती है। और मुद्रा का मूल्य (Value) घट जाता है।

वस्तु की मांग ↑ + वस्तु की आपूर्ति ↓ ⇒ वस्तु की कीमत ↑
(मुद्रास्फीति)

तरलता के आधार पर मुद्रा स्फीति को चार भाग में बाँटते हैं—

- रेंगती मुद्रा स्फीति
- चलती मुद्रा स्फीति
- दौड़ती मुद्रा स्फीति
- अति मुद्रा स्फीति

मुद्रा स्फीति (महंगाई) के उत्पत्ति के तीन कारण है—

(i) तरलता में वृद्धि

Eg :- वेनेजुएला

(ii) लगातार प्रेरित मुद्रा स्फीति

- इसमें लागत बढ़ जाता है, जिस कारण महंगाई बढ़ जाती है।

Eg :- कोयला का रेट बढ़ना, चाय का महंगा होना।

Note :- लगातार प्रेरित मुद्रा अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि यह स्थाई रहती है। मुद्रा स्फीति में मुद्रा बढ़ जाता है जिस कारण कार्य शक्ति, मांग तथा महंगाई तीनों बढ़ जाता है, किन्तु मुद्रा का मूल्य घट जाता है। जिस कारण रोजगार पर लगा व्यक्ति भी बाजार कीमत पर रोजगार नहीं पा पाता है और बेरोजगारी का स्तर बढ़ जाता है।

(iii) माँग प्रेरित मुद्रा स्फीति

- इसमें माँग के बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है।

Eg :- लगन में D.J, ईद में सेवई

➤ मुद्रा स्फीति से लाभ

- ऋण (देनदार), किसान, उद्योगपति व्यापारी, परिवर्तित आय वाला व्यक्ति, विक्रेता, निर्यातक

➤ मुद्रा स्फीति से हानि

- ऋणदाता (लेनदार), स्थिर आय वाला व्यक्ति, ग्राहक, आयतक
- मुद्रा स्फीति को रोकने के उपाय को अपस्फीति कहते हैं। इसे रोकने के लिए प्रतिभूति की बिक्री तथा उत्पादन को बढ़ा देना चाहिए। तथा मौद्रिक नीति को कठोर कर देना चाहिए।

➤ मंदी (Recession)

- मंदी वह स्थिति है जिसमें तरलता अत्यधिक घट जाती है। जिस कारण व्यापार प्रभावित हो जाता है।
- अधिक देर तक मंदी रहने से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

➤ मंदीगत मुद्रास्फीति/निस्पंदन (Stagflation)

- जब मंदी तथा मुद्रास्फीति दोनों एक साथ हो जाए तो उसे मंदीगत मुद्रास्फीति/निस्पंदन कहते हैं। इस स्थिति में पहले मंदी को ठीक करने के लिए तरलता बढ़ा देना चाहिए उसके बाद मुद्रा स्फीति को ठीक करना चाहिए।

➤ धारणीय मुद्रास्फीति (Sustainable Inflation)

- यह ऐसी मुद्रास्फीति दर है जिसमें अर्थव्यवस्था एक उच्च विकास दर पर गतिमान रहती है।
- इस प्रकार के मुद्रास्फीति में आम लोगों को कोई विशेष समस्या नहीं होती है।

➤ मुद्रास्फीति की गणना

- भारत में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल सूचकांक के आधार पर की जाती है।

- वर्तमान में मुद्रास्फीति की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में वर्ष 2011-12 का प्रयोग किया जाता है।

➤ मुद्रास्फीति की सूचक

● थोक मूल सूचकांक (Wholesale Price Index)

WPI – यह वस्तुओं के थोक मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।

● उपभोक्ता मूल सूचकांक (Consumer Price Index) CPI

– यह प्रतिदिन उपयोग में लाए जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि की गणना करता है।

Note :- फिलिप्स वक्र (Phillips Curve)– इसका प्रतिपादन न्यूजीलैण्ड अर्थशास्त्री A.W. Phillips द्वारा किया गया था। इसमें बेरोजगारी की दर, मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि दर तथा मुद्रास्फीति की दर में संबंध को बताता है।

➤ नोट का निर्गमन

- ☛ 1 रु. के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं जब की उससे ऊपर के मूल्य के नोट पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है।
- ☛ नोट जारी करने के लिए RBI आरक्षित कोष प्रणाली को अपनाती थी जिसके तहत RBI को 400 करोड़ मूल्य रखना होता था। जिसमें 215 करोड़ मूल्य का भारतीय रुपया या सोना रखा जाता था, जबकि शेष 185 करोड़ मूल्य का विदेशी मुद्रा रखा जाता था।
- ☛ वर्तमान में RBI नोट छापने के लिए न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली को अपनाती है। इसके तहत RBI को 200 करोड़ रुपया रखने होते हैं। इसमें 115 करोड़ मूल्य का भारतीय रुपया, या सोना होता है। जबकि शेष 85 करोड़ मूल्य का विदेशी मुद्रा रखनी होती है।
- ☛ भारत में नोट छापने के चार प्रेस हैं। जिसमें देवास तथा नासिक के प्रेस केन्द्र सरकार के अधीन हैं। जबकि हैदराबाद तथा साहबानी के प्रेस RBI के अधीन हैं।

➤ देवास प्रिंटिंग प्रेस (मध्य प्रदेश)

- ☛ यह केन्द्र सरकार का सबसे बड़ा नोट का प्रेस है। इसे बैंक नोट प्रेस कहते हैं। यहाँ 20, 50, 100 तथा 500 के नोट छापते हैं।

➤ नासिक प्रिंटिंग प्रेस

- ☛ इसे Currency नोट प्रेस कहते हैं। यहाँ 10, 50, 100, 500 तथा 2000 के नोट छपते हैं। हैदराबाद तथा साहबानी के प्रेस सबसे आधुनिक हैं। इसमें सभी प्रकार के नोट छपते हैं।

➤ टकसाल (Mint)

- ☛ सिक्का बनाने वाले मशीन को टकसाल कहते हैं। भारत में 5 टकसाल हैं।

(i) मुम्बई (स्थापना - 1830, सबसे पुराना)

(ii) चेरापल्ली तमिलनाडु

(iii) हैदराबाद

(iv) कोलकाता

(v) नोएडा (स्थापना - 1989, सबसे आधुनिक)

Note :- कोलकाता- टकसाल में भारत रत्न तथा शेष पदक एवं तमगा बनता है।

